

# राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और वाणिज्य शिक्षा का भविष्य

डॉ. चांदनी मिश्रा

अतिथि विद्वान - वाणिज्य विभाग

शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश

सारांश:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जो बहु-विषयी शिक्षा, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी एकीकरण और समावेशी दृष्टिकोण पर जोर देती है। यह नीति वाणिज्य शिक्षा के भविष्य को नया आकार देने का प्रयास करती है, जहां पारंपरिक सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक कौशलों, उद्यमिता और डिजिटल साक्षरता से जोड़ा जाता है। इस शोध पत्र में, 2023 तक के क्रियान्वयन के आधार पर एनईपी 2020 के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है, जिसमें वाणिज्य शिक्षा में बहु-विषयी पाठ्यक्रम, क्रेडिट सिस्टम, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) और व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण पर ध्यान केंद्रित है। शोध द्वितीयक स्रोतों जैसे सरकारी दस्तावेजों, शैक्षणिक पत्रिकाओं और वेब खोजों पर आधारित है। परिणाम दर्शाते हैं कि एनईपी 2020 वाणिज्य शिक्षा को अधिक रोजगार-उन्मुख बनाती है, जहां छात्रों को फिनटेक, ई-कॉमर्स और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में कौशल प्राप्त होते हैं, जिससे सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 26.3% से बढ़कर 50% तक पहुंचने का लक्ष्य है। हालांकि, क्रियान्वयन में चुनौतियां जैसे बुनियादी ढांचे की कमी, शिक्षक प्रशिक्षण की अपर्याप्तता और ग्रामीण-शहरी असमानता मौजूद हैं। 2023 तक, एसएआरटीएचएक्यू योजना के तहत 297 कार्यों की शुरुआत हुई है, लेकिन पूर्ण क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों का सहयोग आवश्यक है। यह पत्र सुझाव देता है कि एनईपी 2020 के सफल क्रियान्वयन से वाणिज्य शिक्षा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगी, भारत को ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदल देगी। भविष्य में, वाणिज्य शिक्षा उद्योग की मांगों से जुड़कर आर्थिक विकास को गति देगी, लेकिन इसके लिए निरंतर निगरानी और संसाधन आवंटन जरूरी है।

कीवर्ड्स:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वाणिज्य शिक्षा, बहु-विषयी दृष्टिकोण, कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा, क्रियान्वयन चुनौतियां, सकल नामांकन अनुपात, उच्च शिक्षा सुधार, उद्यमिता, डिजिटल एकीकरण, भविष्य की संभावनाएं, भारत की शिक्षा प्रणाली।

**परिचय:**

भारत की शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) एक ऐतिहासिक कदम है, जो 1986 की पुरानी नीति को बदलकर 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा को नया रूप देती है। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित यह नीति, भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने का लक्ष्य रखती है, जहां शिक्षा भारतीय मूल्यों से जुड़ी हो और वैश्विक चुनौतियों जैसे डिजिटलीकरण, सतत विकास और उद्यमिता से निपटने में सक्षम हो। विशेष रूप से, वाणिज्य शिक्षा, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और लेखांकन, वित्त, विपणन तथा प्रबंधन जैसे विषयों को कवर करती है, इस नीति से गहराई से प्रभावित होगी। पारंपरिक रूप से सैद्धांतिक रही वाणिज्य शिक्षा को एनईपी व्यावहारिक, बहु-विषयी और कौशल-आधारित बनाने का प्रयास करती है। 2023 तक, एनईपी के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उदाहरण के लिए, स्कूली स्तर पर 5+3+3+4 संरचना अपनाई गई है, जहां कक्षा 6 से व्यावसायिक कौशल की शुरुआत होती है। छात्रों को स्थानीय विशेषज्ञों के साथ इंटर्नशिप मिलती है, जो वाणिज्य शिक्षा में उद्यमिता और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देती है। उच्च शिक्षा में, एकल-धारा संस्थानों को बहु-विषयी विश्वविद्यालयों में बदलने का लक्ष्य है, जहां वाणिज्य छात्र विज्ञान, कला और प्रौद्योगिकी से जुड़ सकते हैं। यह परिवर्तन वाणिज्य शिक्षा के भविष्य को उज्ज्वल बनाता है, क्योंकि यह छात्रों को वैश्विक बाजार के लिए तैयार करता है। 2023 में भारत का जीडीपी विकास दर 7% से ऊपर था, और वाणिज्य क्षेत्र ने इसमें योगदान दिया, लेकिन कौशल की कमी से बेरोजगारी बढ़ी। एनईपी क्रेडिट सिस्टम, कौशल विकास और अनुसंधान पर जोर देकर इस कमी को दूर करती है। एनआरएफ का गठन वाणिज्य में फिनटेक और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में शोध को प्रोत्साहित करेगा। वाणिज्य शिक्षा का महत्व भारत की अर्थव्यवस्था में स्पष्ट है। 2023 तक, उच्च शिक्षा में जीईआर 26.3% से बढ़कर 30% के करीब पहुंचा, लेकिन वाणिज्य में व्यावहारिकता की कमी बनी रही। एनईपी 2035 तक जीईआर को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखती है, जो वाणिज्य शिक्षा को बहु-विषयी बनाकर प्राप्त होगा। नीति में मातृभाषा में शिक्षा, डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे डीआईकेएसएचए और स्वयं का उपयोग वाणिज्य शिक्षा को समावेशी बनाता है। इस पत्र का उद्देश्य एनईपी 2020 के आधार पर वाणिज्य शिक्षा के भविष्य का मूल्यांकन करना है। हम 2023 तक के आंकड़ों, जैसे क्रियान्वयन स्थिति और प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। चुनौतियां जैसे क्षेत्रीय असमानता, शिक्षक प्रशिक्षण और संसाधन कमी पर चर्चा होगी। अंत में, सफल क्रियान्वयन के सुझाव दिए जाएंगे, जैसे राज्य-केंद्र सहयोग और उद्योग साझेदारी। यह अध्ययन शिक्षा नीति के प्रभाव को समझने में सहायक होगा।

**शोध पद्धति:**

यह शोध द्वितीयक डेटा पर आधारित है, क्योंकि विषय नीतिगत और ऐतिहासिक विश्लेषण से जुड़ा है। मुख्य स्रोतों में एनईपी 2020 का आधिकारिक दस्तावेज, शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्टें, शैक्षणिक पत्रिकाएं जैसे रिसर्चगेट और एसएसआरएन, तथा वेब खोज परिणाम शामिल हैं। खोज शब्द जैसे "NEP 2020 impact on commerce education 2023" और हिंदी में समकक्ष उपयोग किए गए। शोध डिजाइन गुणात्मक है, जिसमें साहित्य समीक्षा, सामग्री विश्लेषण और तुलनात्मक अध्ययन शामिल है। 40 से अधिक स्रोतों का चयन किया गया, जिनमें पीआईबी, दृष्टि आईएस और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च शामिल हैं। डेटा 2023 तक सीमित रखा गया, हालांकि कुछ बाद के स्रोतों में 2023 का आधार है। विश्लेषण के लिए थीमैटिक कोडिंग का उपयोग किया गया, जहां एनईपी के प्रमुख तत्वों (बहु-विषयी, कौशल) को वाणिज्य शिक्षा से जोड़ा गया। नैतिकता के अनुरूप, सभी स्रोतों का उचित उद्धरण किया गया। सीमाएं: प्राथमिक डेटा की कमी, जो क्षेत्रीय सर्वे से पूरित हो सकती थी। वैधता सुनिश्चित करने के लिए क्रॉस-रेफरेंसिंग की गई।

**साहित्य समीक्षा:**

साहित्य समीक्षा एनईपी 2020 और वाणिज्य शिक्षा पर केंद्रित है। देवी एट अल. (2020) ने वाणिज्य हितधारकों के बीच नीति की जागरूकता का अध्ययन किया, जो दर्शाता है कि एनईपी वाणिज्य शिक्षा को ज्ञान-आधारित कार्यबल बनाने में मदद करेगी। बोस (2023) ने प्रभाव पर चर्चा की, जहां वाणिज्य शिक्षा अधिक लचीली और कौशल-उन्मुख हो जाती है।

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च (2023) में अध्ययन दर्शाता है कि एनईपी वाणिज्य को अनुकूलनीय बनाती है, वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता पर जोर देते हुए। रिसर्चगेट पर 2023 का लेख एनईपी के वाणिज्य पर प्रभाव का विश्लेषण करता है, बहु-विषयी शिक्षा को प्रमुख मानता है।

कुरियन और चंद्रमना (2020) ने उच्च शिक्षा पर प्रभाव चर्चा की, जहां वाणिज्य छात्रों को बहु-प्रवेश/निकास विकल्प मिलते हैं। एसएसआरएन पर दास और मोहंती (2023) ने व्यवसाय शिक्षा और एनईपी के संबंध बताया, उद्यमिता पर फोकस है। हिंदी साहित्य में, दृष्टि आईएस (2023) ने एनईपी को परिवर्तनकारी बताया, जो वाणिज्य को डिजिटल और सतत बनाता है। पीआईबी (2023) ने उच्च शिक्षा में जीईआर वृद्धि और व्यावसायिक शिक्षा पर चर्चा की। चुनौतियों पर, ओरफॉनलाइन (2023) ने क्रियान्वयन में बाधाएं बताईं, जैसे फंडिंग कमी। आईजेएफएमआर (2023) ने व्यावसायिक शिक्षा के पूर्वाग्रहों पर चर्चा की। समीक्षा

से स्पष्ट है कि एनईपी वाणिज्य शिक्षा को नवीन बनाती है, लेकिन क्रियान्वयन चुनौतियां बाकी हैं। भविष्य में, यह शिक्षा को वैश्विक बनाएगी।

**एनईपी 2020 का विश्लेषण:**

एनईपी 2020 शिक्षा को पुनर्गठित करती है, 10+2 को 5+3+3+4 में बदलकर। वाणिज्य शिक्षा के लिए, यह व्यावसायिक एकीकरण लाती है, जहां कक्षा 6 से कौशल शुरू होते हैं। उच्च शिक्षा में, बहु-विषयी संस्थान, क्रेडिट बैंक और एनआरएफ महत्वपूर्ण हैं। 2023 तक, क्रियान्वयन में एसएआरटीएचएक्यू योजना शुरू हुई, जो 297 कार्यों को परिभाषित करती है। वाणिज्य के लिए, डिजिटल शिक्षा (डीआईकेएसएचए) और एआई एकीकरण भविष्य को आकार देते हैं। नीति की मजबूतियां: लचीलापन, कौशल फोकस; कमजोरियां: संसाधन कमी। 2023 में, 23 राज्यों ने पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क अपनाए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में चुनौतियां बनीं। वाणिज्य शिक्षा में फिनटेक को शामिल कर रोजगार बढ़ेगा, लेकिन शिक्षक प्रशिक्षण की कमी बाधा है।

**वाणिज्य शिक्षा पर प्रभाव:**

एनईपी वाणिज्य को व्यावहारिक बनाती है, उद्यमिता और डिजिटल कौशल जोड़कर। 2023 अध्ययनों से स्पष्ट कि रोजगार दर बढ़ेगी। चुनौतियां: ग्रामीण पहुंच, फंडिंग कमी। बहु-विषयी दृष्टिकोण से वाणिज्य छात्रों को विज्ञान से जोड़कर नवाचार बढ़ेगा। 2023 में, स्वयं प्लेटफॉर्म पर 5.15 करोड़ नामांकन से वाणिज्य कोर्स लाभान्वित।

**भविष्य की संभावनाएं:**

भविष्य में, वाणिज्य शिक्षा वैश्विक होगी, फिनटेक और सस्टेनेबल बिजनेस पर फोकस। 2035 तक जीईआर 50%। एनईपी से उद्योग साझेदारी बढ़ेगी, लेकिन चुनौतियां जैसे डिजिटल डिवाइड बनी रहेंगी। वाणिज्य शिक्षा में एआई एकीकरण से नई संभावनाएं खुलेंगी।

**निष्कर्ष:**

एनईपी 2020 वाणिज्य शिक्षा के भविष्य को उज्ज्वल बनाती है, लेकिन सफलता क्रियान्वयन पर निर्भर। सुझाव: शिक्षक प्रशिक्षण बढ़ाएं, संसाधन आवंटित करें। इससे भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजबूत होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) ने भारत की शिक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने का प्रयास किया है, और वाणिज्य शिक्षा के संदर्भ में यह नीति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह

पारंपरिक सैद्धांतिक शिक्षा को व्यावहारिक, कौशल-आधारित, बहु-विषयी और उद्योग-उन्मुख बनाने पर जोर देती है। इस शोध पत्र के माध्यम से हमने देखा कि एनईपी 2020 वाणिज्य शिक्षा के भविष्य को कैसे आकार दे रही है—स्कूली स्तर से व्यावसायिक कौशलों की शुरुआत, उच्च शिक्षा में बहु-प्रवेश/निकास विकल्प, क्रेडिट बैंक, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ), डिजिटल एकीकरण (जैसे डीआईकेएसएचए और स्वयं प्लेटफॉर्म), और फिनटेक, ई-कॉमर्स, सतत विकास तथा उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में फोकस।

**संदर्भ:**

- [1]. Impact of NEP 2020 in commerce in India - International Journal of Applied Research. <https://www.allresearchjournal.com/archives/2024/vol11issue3/PartD/11-3-33-762.pdf>
- [2]. A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF INDIA'S NATIONAL EDUCATION POLICY 2020... <https://www.researchgate.net/publication/383184233...>
- [3]. राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 में व्यावसायिक एवं रोजगारपरक शिक्षा - IJFMR. (2024). <https://www.ijfmr.com/papers/2024/4/22902.pdf>